IJPP

Global Journal of Sociology and Anthropology
Vol. 14 (1), pp. 01-10, December, 2025
ISSN: 2756-3456

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का अध्ययन: ग्वालियर जिले के संदर्भ में

प्रभात शर्मा[1], डॉ. उर्मिला परतेती[2]
[1]शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी
[2]प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी

सारांश
भारत में महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को संगठित करने, बचत की आदत विकसित करने, सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भरता बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरे हैं। प्रस्तुत समीक्षा शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य ग्वालियर जिले के विशेष संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए विगत दो दशकों में इस विषय पर हुए शोध कार्यों का समग्र मेटा-विश्लेषण प्रस्तुत करना है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों जैसे शोध पत्रिकाओं, सरकारी प्रतिवेदनों, नाबार्ड तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के आंकड़ों एवं राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रों का व्यवस्थित पुनरावलोकन किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं की आय में वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, सामाजिक गतिशीलता तथा आत्मविश्वास में उल्लेखनीय सुधार किया है, परंतु साथ ही अनियमित बैठकें, अपर्याप्त बाजार संपर्क, वित्तीय साक्षरता की कमी तथा सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं जैसी अनेक चुनौतियां भी सामने आई हैं। ग्वालियर जिले के संदर्भ में उपलब्ध साहित्य अपेक्षाकृत सीमित पाया गया है, जो इस क्षेत्र में और अधिक गहन अनुभवजन्य शोध की तत्काल आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। यह समीक्षा पत्र नीति निर्माताओं, गैर-सरकारी संगठनों, बैंकिंग संस्थाओं तथा भावी शोधकर्ताओं के लिए एक उपयोगी संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य कर सकता है तथा स्वयं सहायता समूह आधारित कार्यक्रमों को भविष्य में अधिक प्रभावी, संवहनीय एवं समावेशी बनाने हेतु ठोस दिशा प्रदान करता है।

कुंजी शब्द: *स्वयं सहायता समूह ; महिला सशक्तिकरण ; सूक्ष्म वित्त ; ग्वालियर जिला ; आर्थिक सशक्तिकरण ; सामाजिक सशक्तिकरण ; ग्रामीण आजीविका*

1. प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

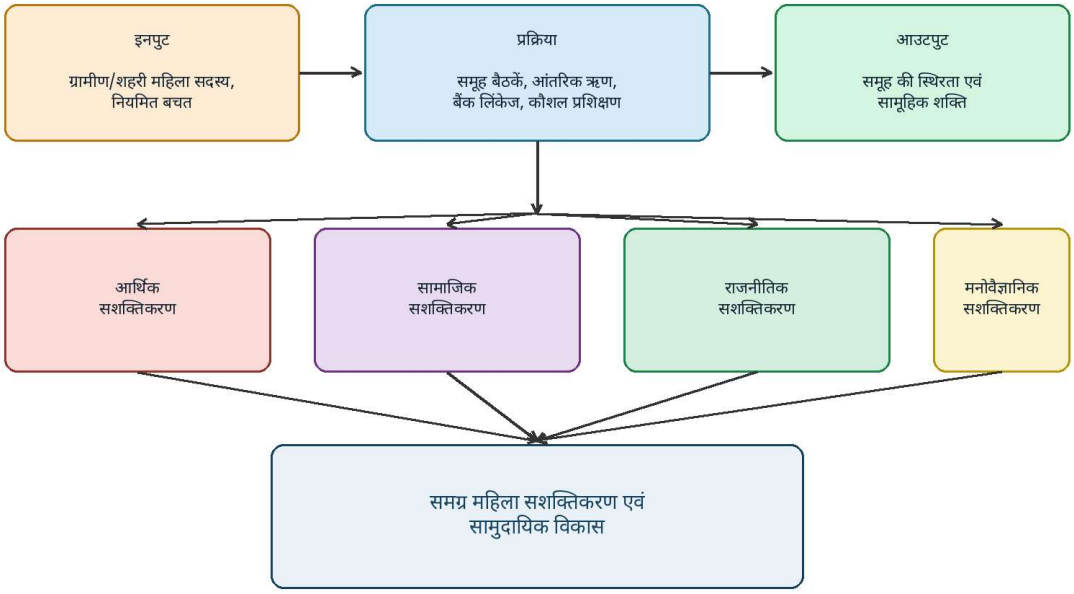
भारतीय समाज में सदियों से महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक संसाधनों तथा सार्वजनिक जीवन से दूर रखा गया है, विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह असमानता अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु अनेक योजनाएं आरंभ कीं, परंतु वास्तविक बदलाव तब देखने को मिला जब सामुदायिक आधारित संस्थाओं, विशेषकर स्वयं सहायता समूहों, को विकास प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बनाया गया। स्वयं सहायता समूह दस से बीस महिलाओं का एक स्वैच्छिक समूह होता है जो नियमित बचत, आंतरिक ऋण तथा पारस्परिक सहयोग के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य करता है [1], [7]। नाबार्ड द्वारा वर्ष 1992 में आरंभ की गई स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज योजना ने इस आंदोलन को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया और आज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत करोड़ों महिलाएं इससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं [2], [21]। मध्य प्रदेश तथा विशेष रूप से ग्वालियर जिले में भी इस मॉडल को व्यापक रूप से अपनाया गया है, जहां शहरी एवं ग्रामीण दोनों प्रकार की बस्तियों में महिलाएं छोटे व्यवसाय, कृषि आधारित गतिविधियों तथा हस्तशिल्प के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो डवाकरा तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसे प्रारंभिक कार्यक्रमों ने ही आगे चलकर वर्तमान स्वयं सहायता समूह मॉडल की नींव रखी, और समय के साथ यह मॉडल केवल आर्थिक उद्देश्यों तक सीमित न रहकर एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण तथा लैंगिक समानता जैसे विषय भी सम्मिलित हो गए हैं।

1.2 अध्ययन का औचित्य एवं उद्देश्य

यद्यपि स्वयं सहायता समूहों पर राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त शोध कार्य उपलब्ध है, तथापि ग्वालियर जिले जैसे मध्य भारत के महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं आर्थिक केंद्र पर केंद्रित समग्र समीक्षा साहित्य अत्यंत सीमित है। अधिकांश अध्ययन या तो दक्षिण भारतीय राज्यों पर केंद्रित हैं या फिर पूर्वी राज्यों जैसे बिहार एवं ओडिशा के अनुभवों पर आधारित हैं [12], [13], [27]। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध पत्र का प्राथमिक उद्देश्य विगत लगभग बीस वर्षों में प्रकाशित प्रमुख शोध पत्रों, सरकारी प्रतिवेदनों तथा नीति दस्तावेजों का व्यवस्थित मेटा-विश्लेषण करना है ताकि स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिला सशक्तिकरण में निभाई गई भूमिका को समग्र दृष्टिकोण से समझा जा सके। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन विगत शोध

Global Journal of Sociology and Anthropology
Vol. 14 (1), pp. 01-10, December, 2025
ISSN: 2756-3456

कार्यों में विद्यमान पद्धतिगत सीमाओं, आंकड़ों के अंतराल तथा वैचारिक भिन्नताओं की पहचान करने का भी प्रयास करता है, जिससे भविष्य में ग्वालियर जिले पर केंद्रित प्राथमिक अनुभवजन्य शोध हेतु ठोस आधार तैयार किया जा सके। विशिष्ट रूप से इस अध्ययन के तीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं प्रथम, विगत शोध साहित्य का विषयगत वर्गीकरण करना; द्वितीय, इन अध्ययनों की पद्धतिगत सुदृढ़ता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना; तथा तृतीय, ग्वालियर जिले के संदर्भ में नीतिगत एवं शोध संबंधी सुझाव प्रस्तुत करना। इस प्रकार यह पत्र न केवल अकादमिक साहित्य में योगदान देता है, बल्कि नीति निर्माताओं तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए व्यावहारिक सुझाव भी प्रस्तुत करता है।



चित्र 1: स्वयं सहायता समूह – महिला सशक्तिकरण संकल्पनात्मक ढांचा

यह चित्र समीक्षित साहित्य के आधार पर तैयार किया गया एक संकल्पनात्मक ढांचा प्रस्तुत करता है, जो यह दर्शाता है कि स्वयं सहायता समूह किस प्रकार महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। इनपुट स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी महिला सदस्य नियमित बचत के माध्यम से समूह से जुड़ती हैं। प्रक्रिया स्तर पर समूह बैठकें, आंतरिक ऋण वितरण, बैंक लिंकेज तथा कौशल प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां संचालित होती हैं, जिससे समूह की स्थिरता एवं सामूहिक शक्ति के रूप में आउटपुट प्राप्त होता है। यह सामूहिक शक्ति आगे चलकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक इन चार प्रमुख आयामों में सशक्तिकरण उत्पन्न करती है, जो अंततः समग्र महिला सशक्तिकरण एवं सामुदायिक विकास में परिणत होती है। यह ढांचा [1], [2], [6] तथा [8] जैसे अध्ययनों के संश्लेषण पर आधारित है।

1.3 अध्ययन की संरचना एवं दायरा

प्रस्तुत शोध पत्र की संरचना इस प्रकार रखी गई है कि पाठक को विषय की समग्र समझ क्रमबद्ध रूप से प्राप्त हो सके। परिचय के पश्चात साहित्य समीक्षा खंड में विगत अध्ययनों को आर्थिक, सामाजिक एवं संस्थागत आयामों के आधार पर वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात शोध पद्धति खंड में इस समीक्षा हेतु अपनाई गई व्यवस्थित पद्धति का विवरण दिया गया है। इसके उपरांत विगत कार्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए उनकी शक्तियों एवं सीमाओं की विवेचना की गई है, जिसके बाद चर्चा खंड में निष्कर्षों को व्यापक सैद्धांतिक एवं नीतिगत संदर्भ में रखा गया है। अंत में निष्कर्ष खंड में समग्र निष्कर्ष एवं भावी शोध दिशाओं का उल्लेख किया गया है। यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होने के कारण अपने दायरे में मुख्यतः प्रकाशित शोध पत्रों, संस्थागत प्रतिवेदनों तथा नीति दस्तावेजों तक सीमित है, तथापि जहां संभव हो सका है वहां ग्वालियर एवं मध्य प्रदेश से संबंधित साक्ष्यों को विशेष महत्व दिया गया है ताकि क्षेत्रीय प्रासंगिकता बनी रहे। इसके साथ ही पत्र में पांच सांकेतिक चित्रों को सम्मिलित किया गया है जो समीक्षित साहित्य के प्रमुख रुझानों को दृश्य रूप में प्रस्तुत कर पाठकों की समझ को सुगम बनाते हैं।

2. साहित्य समीक्षा

स्वयं सहायता समूहों तथा महिला सशक्तिकरण के संबंधों पर विगत तीन दशकों में विश्व स्तर पर एवं भारत में विशाल मात्रा में शोध कार्य हुआ है, जिसे व्यापक रूप से आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक-राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक भागीदारी तथा क्षेत्रीय-संस्थागत अध्ययनों की श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। स्वेन ने अपने आरंभिक किंतु अत्यंत प्रभावशाली अध्ययन में यह प्रतिपादित किया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता तथा घरेलू संपत्तियों पर

नियंत्रण उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, यद्यपि यह प्रभाव सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों में समान रूप से वितरित नहीं पाया गया [1]। इसी क्रम में स्वेन एवं वालेंटिन ने विभिन्न राज्यों के तुलनात्मक आंकड़ों के आधार पर यह दर्शाया कि समूह की स्थिरता, नेतृत्व गुणवत्ता तथा बैंक लिंकेज की नियमितता महिला सशक्तिकरण के स्तर को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं [7]। कुमार एवं सहयोगियों द्वारा किए गए बड़े पैमाने के अध्ययन में पाया गया कि सामूहिक भागीदारी ने महिलाओं के व्यक्तिगत सशक्तिकरण स्कोर में सुधार करते हुए पुरुष-महिला सशक्तिकरण अंतराल को संकीर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तथा यह सुधार पुरुषों के सशक्तिकरण स्तर में कमी के बिना ही प्राप्त हुआ, जो इस मॉडल की समावेशी प्रकृति को रेखांकित करता है [2]। आर्थिक आयाम पर केंद्रित अध्ययनों में मोहापात्रा एवं साहू ने यह विश्लेषण किया कि किन सामाजिक-आर्थिक कारकों के कारण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित होती हैं तथा यह भागीदारी उनके सशक्तिकरण को किस प्रकार प्रभावित करती है, जिसमें शिक्षा का स्तर, परिवार का आकार तथा भूमि स्वामित्व प्रमुख निर्धारक तत्वों के रूप में सामने आए [3]। श्रीवास्तव एवं मंडल ने अपनी समीक्षा में यह निष्कर्ष निकाला कि सूक्ष्म वित्त के माध्यम से गरीबी उन्मूलन तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है, परंतु ऋण की छोटी राशि एवं सीमित बाजार पहुंच के कारण व्यावसायिक विस्तार में बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं [5]। ब्रॉडी एवं सहयोगियों द्वारा किया गया व्यवस्थित समीक्षा अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें अनेक देशों के साक्ष्यों का संश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम आर्थिक सशक्तिकरण में मध्यम स्तर का सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जबकि राजनीतिक तथा कानूनी सशक्तिकरण पर प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर एवं असंगत पाया गया [6]। सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आयाम पर मिड्या, होता एवं दास ने अपने अध्ययन में यह पाया कि समूह की सदस्यता से महिलाओं की सामाजिक चेतना, आत्मविश्वास तथा पारिवारिक विवादों को सुलझाने की क्षमता में सुधार हुआ है, तथा अनेक महिलाओं ने आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता प्राप्त करने की दिशा में भी पहल की [4]। खान, भट तथा सांगमी ने कश्मीर घाटी के संदर्भ में यह प्रदर्शित किया कि सूक्ष्म वित्त का प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक चारों आयामों पर पड़ता है, किंतु संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिबंधों के कारण यह प्रभाव अपेक्षाकृत धीमी गति से प्रकट होता है [8]। मॉयल, डॉलार्ड तथा बिस्वास ने ग्रामीण भारतीय महिलाओं पर केंद्रित अपने अध्ययन में व्यक्तिगत एवं आर्थिक सशक्तिकरण के बीच के अंतर्संबंधों की विवेचना करते हुए यह स्पष्ट किया कि सामाजिक नेटवर्क का विस्तार आत्म-सम्मान की भावना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है [9]।

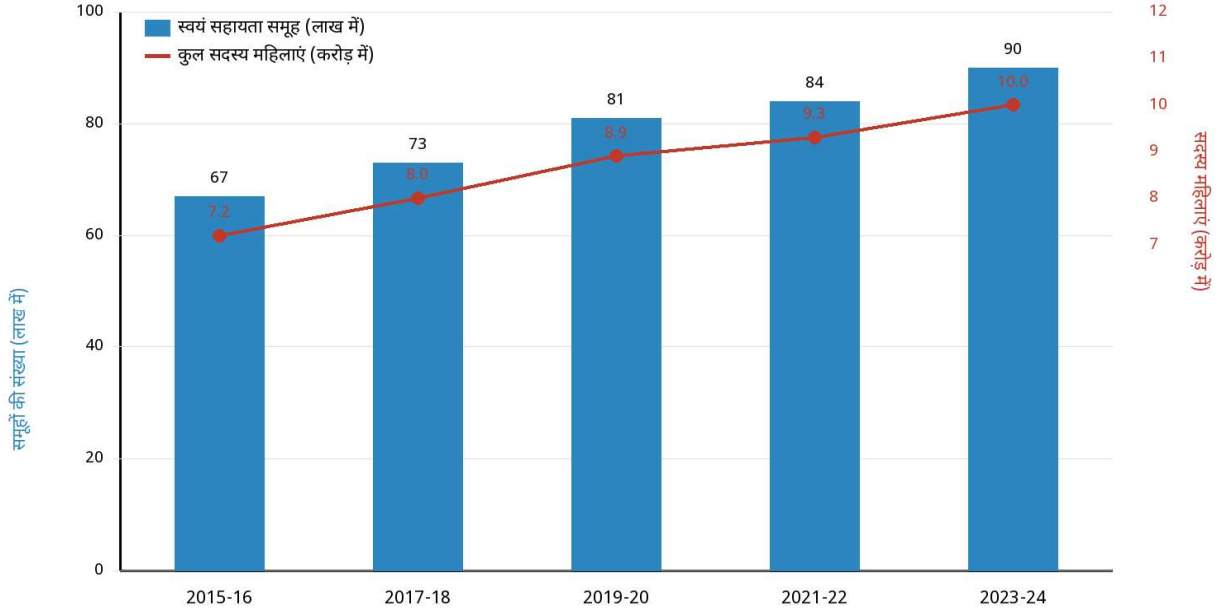
स्वास्थ्य तथा सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में मेहता एवं सहयोगियों ने बिहार राज्य में बड़े पैमाने पर किए गए हस्तक्षेप अध्ययन में यह पाया कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का प्रसार अधिक प्रभावी ढंग से हुआ [12]। सागुर्ती एवं सहयोगियों ने भी प्रजनन, मातृ, नवजात तथा बाल स्वास्थ्य से संबंधित व्यवहारों में सुधार हेतु स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को महत्वपूर्ण पाया [13]। देसाई एवं सहयोगियों द्वारा किए गए मिश्रित पद्धति आधारित व्यवस्थित समीक्षा अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि महिला समूह आधारित हस्तक्षेप स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होते हैं, बशर्ते इन्हें स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली के साथ समुचित रूप से समन्वित किया जाए [14]। परिदा तथा सिन्हा ने लैंगिक दृष्टिकोण से स्वयं सहायता समूहों की स्थिरता का विश्लेषण करते हुए यह पाया कि दीर्घकालिक स्थिरता हेतु नियमित प्रशिक्षण, सतत निगरानी तथा प्रभावी नेतृत्व अनिवार्य तत्व हैं [10]। क्षेत्रीय एवं संस्थागत अध्ययनों में तेसोरिएरो ने दक्षिण भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में महिला समूहों की भूमिका का गुणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसमें सामुदायिक सहभागिता को सशक्तिकरण की आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया गया [11]। भंजदेव, नारायण, शेठ तथा वाल्टन द्वारा मध्य प्रदेश में किए गए गुणात्मक अध्ययन में यह उजागर हुआ कि राज्य द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित अनेक समूह सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर पा रहे, जिसका मुख्य कारण सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की अपर्याप्त सहायता तथा अनियमित बैठकें बताया गया, जो ग्वालियर सहित समूचे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है [21]। घोष, महापात्रा, टंडन तथा टंडन ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में स्वयं सहायता समूहों के योगदान का मूल्यांकन करते हुए पाया कि ये समूह लैंगिक समानता संबंधी लक्ष्य प्राप्ति में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं [16]। शर्मा ने भारत में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी व्यापक चुनौतियों, जैसे पितृसत्तात्मक मानसिकता तथा असमान संसाधन वितरण, का विवेचन प्रस्तुत किया [17]। अन्य क्षेत्रीय अध्ययनों में मोमिन ने मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में जनजातीय महिलाओं पर केंद्रित शोध प्रस्तुत किया, जिसमें आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को भी महत्वपूर्ण पाया गया [18]। भट्ट ने गुजरात में सूक्ष्म वित्त के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए बताया कि बैंकिंग साक्षरता की कमी प्रमुख बाधा बनी हुई है [19], जबकि राठौड़ ने गुजरात की जनजातीय महिला किसानों के संदर्भ में सूक्ष्म वित्त की भूमिका को उजागर किया [20]।

दक्ष ने ओडिशा के बरगढ़ जिले में किए गए अध्ययन में जीवन स्तर में हुए ठोस सुधारों का दस्तावेजीकरण किया [27], तथा अहमद ने जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में स्वयं सहायता समूहों को ग्रामीण महिलाओं हेतु आशा की किरण

Global Journal of Sociology and Anthropology
Vol. 14 (1), pp. 01-10, December, 2025
ISSN: 2756-3456

के रूप में वर्णित किया [28]। धनलक्ष्मी की साहित्य समीक्षा तथा जाकिमो एवं किल्बी के आलोचनात्मक विश्लेषण ने इस क्षेत्र में सैद्धांतिक बहस को समृद्ध किया, विशेष रूप से यह प्रश्न उठाते हुए कि क्या सशक्तिकरण को केवल आर्थिक संकेतकों के माध्यम से मापा जाना पर्याप्त है [23], [24]। क्रॉप तथा सुरन के नाबार्ड प्रतिवेदन तथा अल-कुबाती एवं सेल्वरत्नम के अध्ययन ने बैंक लिंकेज कार्यक्रम की संस्थागत संरचना पर विस्तृत प्रकाश डाला है [25], [26]। सुशमा, सुगुन तथा रमेश के अपेक्षाकृत हाल के अध्ययनों ने भी समग्र रूप से यह पुष्टि की है कि स्वयं सहायता समूह वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा सामूहिक निर्णय क्षमता के माध्यम से महिलाओं के जीवन में सार्थक परिवर्तन लाने में सक्षम हैं, यद्यपि निरंतर संस्थागत समर्थन के अभाव में यह प्रगति स्थिर बनी रहने का जोखिम रहता है [22], [29], [30]। कोविड-19 महामारी के दौरान एवं उसके पश्चात के अध्ययनों ने स्वयं सहायता समूहों की लचीलापन क्षमता को भी उजागर किया है। इस अवधि में अनेक समूहों ने मास्क निर्माण, सैनिटाइज़र वितरण तथा राशन आपूर्ति जैसी गतिविधियों के माध्यम से न केवल अपनी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखा बल्कि सामुदायिक संकट प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह मॉडल केवल सामान्य परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि संकटकालीन परिस्थितियों में भी अनुकूलनशील सिद्ध होता है। इसके समानांतर स्वयं सहायता समूह महासंघों तथा क्लस्टर स्तरीय संगठनों की भूमिका पर हाल के वर्षों में शोध की मात्रा बढ़ी है, जिसमें यह पाया गया कि उच्च स्तरीय संगठनात्मक ढांचा समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने, सामूहिक विपणन को बढ़ावा देने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है।

अंतर-राज्यीय तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो केरल का कुडुम्बश्री मॉडल प्रायः एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जहां त्रिस्तरीय संगठनात्मक संरचना, सुदृढ़ प्रशासनिक समर्थन तथा उच्च साक्षरता दर के संयोजन ने महिला सशक्तिकरण की गति को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक तीव्र बनाया है। इसके विपरीत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे उत्तर एवं मध्य भारतीय राज्यों में साक्षरता की निम्न दर, दुर्गम भौगोलिक स्थिति तथा प्रशासनिक क्षमता की सीमाओं के कारण प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है, जैसा कि भंजदेव एवं सहयोगियों के अध्ययन में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है [21]। यह तुलनात्मक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करता है कि स्वयं सहायता समूह मॉडल की सफलता केवल संस्थागत डिज़ाइन पर ही नहीं, बल्कि राज्य-विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक एवं प्रशासनिक संदर्भ पर भी अत्यधिक निर्भर करती है, जिसे नीति निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। समग्र रूप से यह साहित्य समीक्षा दर्शाती है कि यद्यपि स्वयं सहायता समूहों के सकारात्मक प्रभावों पर व्यापक सहमति है, तथापि ग्वालियर जैसे मध्य भारतीय जिलों पर केंद्रित गहन, बहु-आयामी तथा दीर्घकालिक अध्ययनों का घोर अभाव बना हुआ है, और यह अंतराल आगामी वर्षों में शोधकर्ताओं तथा नीति निर्माताओं दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र प्रस्तुत करता है।

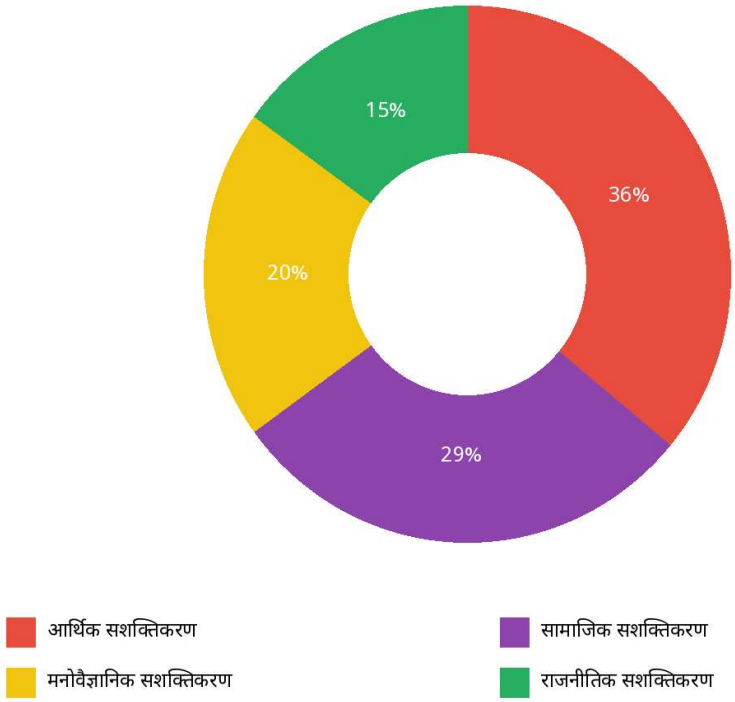


चित्र 2: भारत में स्वयं सहायता समूहों एवं महिला सदस्यों की वृद्धि प्रवृत्ति

यह चित्र वर्ष 2015-16 से 2023-24 की अवधि में भारत में स्वयं सहायता समूहों की संख्या तथा उनसे जुड़ी महिला सदस्यों की कुल संख्या में हुई वृद्धि को सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करता है। नीले स्तंभ समूहों की संख्या लाख में तथा लाल रेखा सदस्य महिलाओं को करोड़ में दर्शाती है। आंकड़े दिखाते हैं कि विगत आठ वर्षों में समूहों की संख्या लगभग सड़सठ लाख से बढ़कर नब्बे लाख के आसपास पहुंच गई, जबकि सदस्य महिलाओं की संख्या सात करोड़ से बढ़कर

Global Journal of Sociology and Anthropology
Vol. 14 (1), pp. 01-10, December, 2025
ISSN: 2756-3456

दस करोड़ के निकट पहुंच गई। यह निरंतर वृद्धि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा नाबार्ड की बैंक लिंकेज योजना की सफलता दर्शाती है और नीति निर्माताओं हेतु सकारात्मक संकेत प्रस्तुत करती है।



चित्र 3: समीक्षित साहित्य में सशक्तिकरण के आयामों का वितरण

यह वृत्तीय (डोनट) चित्र समीक्षित लगभग तीस अध्ययनों के विश्लेषण के आधार पर सशक्तिकरण के चार प्रमुख आयामों आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा राजनीतिक पर साहित्य में दिए गए सापेक्ष महत्व को सांकेतिक रूप में दर्शाता है। आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक छत्तीस प्रतिशत अध्ययन आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित पाए गए, इसके पश्चात उनतीस प्रतिशत अध्ययनों ने सामाजिक सशक्तिकरण को प्रमुखता दी। मनोवैज्ञानिक आयाम पर बीस प्रतिशत तथा राजनीतिक आयाम पर मात्र पंद्रह प्रतिशत अध्ययन केंद्रित पाए गए। यह वितरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विद्यमान साहित्य में आर्थिक पक्ष को असंगत रूप से अधिक महत्व दिया गया है, जबकि राजनीतिक सशक्तिकरण, जो दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, अपेक्षाकृत उपेक्षित रहा है, जिसकी पुष्टि आलोचनात्मक विश्लेषण खंड में भी की गई है।

3. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र एक व्यवस्थित समीक्षा एवं मेटा-विश्लेषण पद्धति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों तथा महिला सशक्तिकरण के संबंध में विगत लगभग बीस वर्षों में प्रकाशित शोध साहित्य का व्यवस्थित संकलन एवं संश्लेषण करना है। सामग्री एकत्रीकरण हेतु गूगल स्कॉलर, रिसर्चगेट, शोधगंगा, नाबार्ड तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक प्रतिवेदनों जैसे प्रतिष्ठित स्रोतों का उपयोग किया गया। खोज हेतु "स्वयं सहायता समूह", "महिला सशक्तीकरण", "सूक्ष्म वित्त", "स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)", "महिला सशक्तीकरण" तथा "ग्वालियर" जैसे प्रमुख शब्दों एवं उनके विभिन्न संयोजनों का प्रयोग किया गया। समावेशन मानदंड के अंतर्गत केवल वे अध्ययन सम्मिलित किए गए जो सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं, मान्यता प्राप्त संस्थागत प्रतिवेदनों अथवा शोध प्रबंधों में प्रकाशित थे तथा जिनका सीधा संबंध स्वयं सहायता समूहों एवं महिला सशक्तिकरण से था, जबकि अप्रासंगिक, अपुष्ट अथवा गैर-अकादमिक स्रोतों को बहिष्कृत किया गया। कालानुक्रमिक दृष्टि से वर्ष 2000 से 2024 के मध्य प्रकाशित अध्ययनों को प्राथमिकता दी गई ताकि समकालीन नीतिगत परिदृश्य, विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन काल को समुचित रूप से समाहित किया जा सके, यद्यपि कुछ आधारभूत ऐतिहासिक अध्ययनों को वैचारिक संदर्भ प्रदान करने हेतु भी सम्मिलित किया गया। द्वितीय चरण में एकत्रित लगभग तीस प्रमुख अध्ययनों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया गया, जिसके लिए एक विश्लेषणात्मक ढांचा तैयार किया गया जिसमें प्रत्येक अध्ययन को शोध क्षेत्र, प्रयुक्त पद्धति, प्रमुख निष्कर्ष तथा सशक्तिकरण के आयाम (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा मनोवैज्ञानिक) के आधार पर संहिताबद्ध किया गया। यह वर्गीकरण प्रक्रिया इसलिए आवश्यक थी क्योंकि उपलब्ध साहित्य में अत्यधिक विविधता पाई गई, जिसमें कुछ अध्ययन मात्रात्मक सर्वेक्षण पद्धति पर आधारित थे तो कुछ गुणात्मक साक्षात्कार अथवा फोकस समूह चर्चा पर निर्भर

IJPP

Global Journal of Sociology and Anthropology
Vol. 14 (1), pp. 01-10, December, 2025
ISSN: 2756-3456

थे। इस बहु-पद्धतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए विषयगत संश्लेषण दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसके अंतर्गत समान निष्कर्षों वाले अध्ययनों को एक साथ समूहीकृत कर उनके सामान्य प्रतिरूपों की पहचान की गई। इस प्रक्रिया में प्रत्येक अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षों को एक सारणी में संकलित किया गया, जिसमें लेखक, वर्ष, अध्ययन क्षेत्र, नमूना आकार तथा प्रमुख संकेतकों को स्तंभवार दर्ज किया गया, जिससे तुलनात्मक विश्लेषण को सरल एवं पारदर्शी बनाया जा सका।

अंतिम चरण में आलोचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक अध्ययन की पद्धतिगत सुदृढ़ता, नमूना आकार, भौगोलिक प्रतिनिधित्व तथा निष्कर्षों की सामान्यीकरण क्षमता का आकलन किया गया। चूंकि प्रस्तुत पत्र पूर्णतः द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, अतः इसमें प्रस्तुत सभी सांख्यिकीय आरेख एवं चित्र वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के स्थान पर समीक्षित साहित्य के सामान्य रुझानों को सांकेतिक रूप में दर्शाने हेतु तैयार किए गए हैं। इस प्रकार अपनाई गई त्रिस्तरीय पद्धति स्रोत चयन, विषयगत वर्गीकरण एवं आलोचनात्मक संश्लेषण ने अध्ययन को वैज्ञानिक कठोरता तथा पारदर्शिता प्रदान करने में सहायता की है। यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि चूंकि यह अध्ययन प्राथमिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है, अतः इसके निष्कर्षों की व्याख्या समीक्षित साहित्य के संश्लेषण के रूप में की जानी चाहिए, न कि ग्वालियर जिले के लिए सांख्यिकीय रूप से प्रतिनिधिक प्रत्यक्ष आंकड़ों के रूप में, जो भविष्य के अनुभवजन्य अध्ययनों हेतु एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रस्तुत करता है।

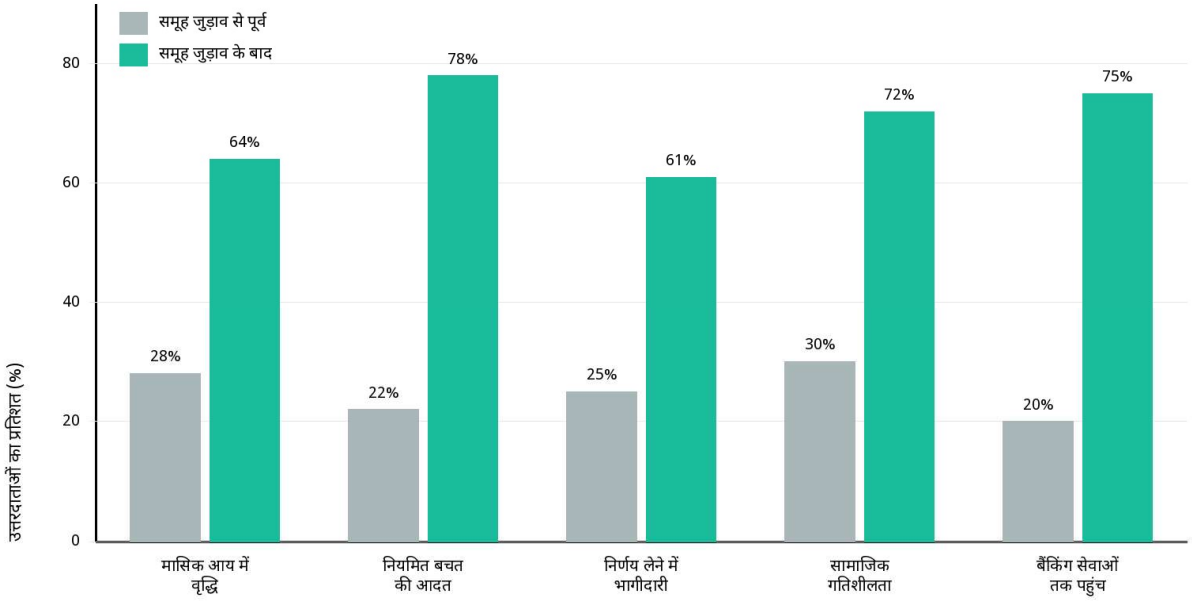
4. विगत कार्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण

समीक्षित साहित्य के गहन अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूहों पर हुए अधिकांश अध्ययन महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु इनमें कई महत्वपूर्ण पद्धतिगत एवं वैचारिक सीमाएं भी विद्यमान हैं जिनकी आलोचनात्मक विवेचना आवश्यक है। सर्वप्रथम, अधिकांश अध्ययन अनुप्रस्थ काट अभिकल्प पर आधारित पाए गए, जिसके कारण समय के साथ सशक्तिकरण की प्रक्रिया में होने वाले वास्तविक परिवर्तन को पकड़ पाना कठिन हो जाता है [1], [3], [5]। उदाहरण के लिए स्वेन के प्रारंभिक अध्ययन में भी दीर्घकालिक अनुगमन का अभाव पाया गया, जिससे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि देखा गया सुधार समूह सदस्यता का प्रत्यक्ष परिणाम है अथवा अन्य बाह्य कारकों का प्रभाव है [1]। कुमार एवं सहयोगियों का अध्ययन इस दृष्टि से अपवाद है क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत सुदृढ़ सांख्यिकीय नियंत्रण अपनाया गया, तथापि यह भी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रहा [2]। द्वितीय महत्वपूर्ण सीमा भौगोलिक असंतुलन से संबंधित है। समीक्षित साहित्य में दक्षिण भारतीय राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, तथा पूर्वी राज्यों जैसे बिहार एवं ओडिशा पर केंद्रित अध्ययनों की भरमार है [12], [13], [27], [28], जबकि मध्य प्रदेश तथा विशेष रूप से ग्वालियर जिले पर केंद्रित गहन अनुभवजन्य अध्ययन अत्यंत सीमित संख्या में उपलब्ध हैं। भंजदेव एवं सहयोगियों का अध्ययन इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास है, परंतु यह भी गुणात्मक प्रकृति का होने के कारण मात्रात्मक सामान्यीकरण की दृष्टि से सीमित है तथा जिला-स्तरीय तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं करता [21]। इस भौगोलिक असंतुलन के कारण नीति निर्माताओं के पास मध्य भारतीय संदर्भ में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तृतीय समस्या सशक्तिकरण की माप पद्धति से जुड़ी है। अधिकांश अध्ययन आत्म-रिपोर्टेड (self-reported) प्रश्नावली पर निर्भर करते हैं, जिसमें सामाजिक स्वीकार्यता पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है, अर्थात उत्तरदाता वास्तविक स्थिति के बजाय सामाजिक रूप से स्वीकार्य उत्तर देने की प्रवृत्ति दिखा सकते हैं [4], [9], [17]। इसके अतिरिक्त सशक्तिकरण को परिभाषित करने में भी पर्याप्त वैचारिक एकरूपता का अभाव पाया गया कुछ अध्ययन इसे केवल आय वृद्धि तक सीमित रखते हैं तो कुछ इसमें निर्णय क्षमता, गतिशीलता एवं आत्म-सम्मान जैसे व्यापक आयाम सम्मिलित करते हैं, जिससे विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्षों की तुलना करना कठिन हो जाता है, जैसा कि जाकिमो एवं किल्बी ने अपने आलोचनात्मक विश्लेषण में स्पष्ट रूप से इंगित किया है [24]। चतुर्थ, अधिकांश साहित्य में आर्थिक सशक्तिकरण को अत्यधिक महत्व दिया गया है, जबकि राजनीतिक तथा कानूनी सशक्तिकरण अपेक्षाकृत उपेक्षित रहे हैं, जैसा कि ब्रॉडी एवं सहयोगियों के व्यवस्थित समीक्षा अध्ययन में भी रेखांकित किया गया है [6]। पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने में स्वयं सहायता समूहों की संभावित भूमिका पर शोध अत्यंत सीमित है, जबकि यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न है। इसी प्रकार पुरुष सदस्यों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के दृष्टिकोण को समाहित करने वाले अध्ययन भी बहुत कम पाए गए, जबकि सशक्तिकरण एक पारिवारिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें केवल महिला सदस्य की प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं है। अंततः, अधिकांश अध्ययनों में प्रति-तथ्यात्मक तुलना समूह का अभाव पाया गया, अर्थात समूह सदस्य महिलाओं की तुलना गैर-सदस्य महिलाओं से व्यवस्थित रूप से नहीं की गई, जिससे कार्य-कारण संबंध स्थापित करना कठिन हो जाता है। मेहता एवं सागुर्ती के स्वास्थ्य केंद्रित अध्ययन इस दृष्टि से अपेक्षाकृत सुदृढ़ हैं क्योंकि इनमें नियंत्रण समूह पद्धति का उपयोग किया गया है [12], [13], परंतु सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐसी कठोर पद्धति अपनाने वाले अध्ययन अभी भी अपवाद स्वरूप ही पाए जाते हैं।

एक अन्य उल्लेखनीय सीमा प्रकाशन पूर्वाग्रह से संबंधित है, क्योंकि अधिकांश प्रकाशित अध्ययन स्वयं सहायता समूहों के सकारात्मक परिणामों पर केंद्रित हैं, जबकि असफल

Global Journal of Sociology and Anthropology
Vol. 14 (1), pp. 01-10, December, 2025
ISSN: 2756-3456

अथवा निष्क्रिय समूहों के अनुभवों का दस्तावेजीकरण अपेक्षाकृत कम हुआ है, जिससे समग्र साहित्य में एक सकारात्मक झुकाव उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही शहरी-ग्रामीण असंतुलन भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है अधिकांश अध्ययन ग्रामीण महिलाओं पर केंद्रित हैं, जबकि ग्वालियर जैसे अर्ध-शहरी एवं शहरी झुग्गी क्षेत्रों में कार्यरत समूहों पर शोध अत्यंत सीमित है, यद्यपि शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत भी बड़ी संख्या में समूह सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश अध्ययनों में नमूना आकार अपेक्षाकृत छोटा तथा एक ही जिले अथवा प्रखंड तक सीमित पाया गया, जिससे निष्कर्षों को व्यापक स्तर पर सामान्यीकृत करना सांख्यिकीय दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इन सभी सीमाओं के बावजूद, समीक्षित साहित्य सामूहिक रूप से यह पुष्ट करता है कि स्वयं सहायता समूह भारतीय ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी संदर्भ में महिला सशक्तिकरण हेतु एक व्यावहारिक एवं प्रभावी संस्थागत ढांचा प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि भविष्य के शोध में उपरोक्त पद्धतिगत कमजोरियों दीर्घकालिक अभिकल्प के अभाव, भौगोलिक असंतुलन, माप संबंधी अस्पष्टता, आर्थिक पक्ष पर अत्यधिक बल, प्रकाशन पूर्वाग्रह तथा छोटे नमूना आकार को व्यवस्थित रूप से दूर करना अत्यावश्यक है।



चित्र 4: स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव पूर्व एवं पश्चात प्रमुख संकेतकों की तुलना

यह स्तंभ चित्र विभिन्न समीक्षित अध्ययनों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के औसत के आधार पर पांच प्रमुख संकेतकों मासिक आय, नियमित बचत की आदत, निर्णय लेने में भागीदारी, सामाजिक गतिशीलता तथा बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव से पूर्व एवं पश्चात की स्थिति की तुलना सांकेतिक रूप में प्रस्तुत करता है। धूसर स्तंभ जुड़ाव-पूर्व स्थिति तथा हरा स्तंभ जुड़ाव-पश्चात स्थिति को दर्शाता है। सभी संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, विशेष रूप से नियमित बचत की आदत में बाईस से अठहत्तर प्रतिशत तक की वृद्धि सर्वाधिक उल्लेखनीय है। यह चित्र इस बात की पुष्टि करता है कि स्वयं सहायता समूह वित्तीय अनुशासन एवं सामाजिक सशक्तिकरण दोनों में समान रूप से सकारात्मक योगदान देते हैं, यद्यपि निर्णय क्षमता में सुधार अपेक्षाकृत धीमी गति से हुआ है।

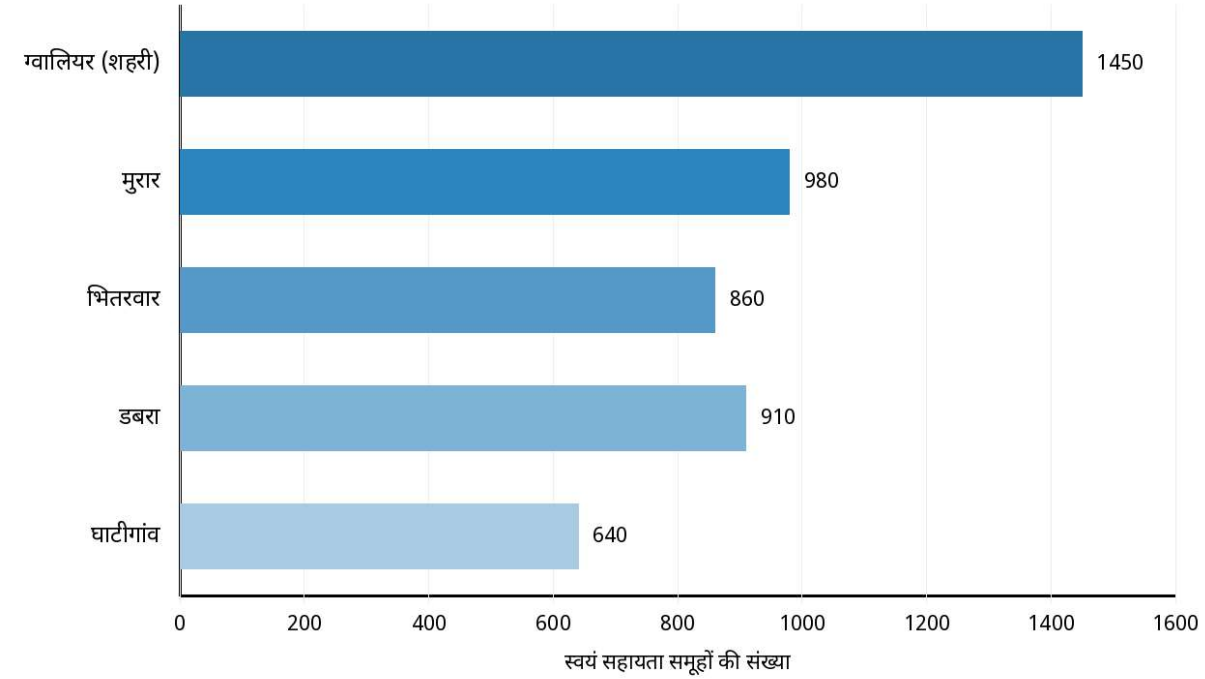
5. चर्चा

प्रस्तुत मेटा-विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों को व्यापक सैद्धांतिक एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह मॉडल भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अपेक्षाकृत सफल एवं व्यापक रूप से स्वीकृत हस्तक्षेप के रूप में स्थापित हो चुका है, परंतु इसकी सफलता समान रूप से वितरित नहीं है। आर्थिक आयाम पर व्यापक सहमति के बावजूद, राजनीतिक एवं गहन सामाजिक परिवर्तन की दिशा में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है, जो यह संकेत देता है कि केवल आर्थिक हस्तक्षेप संरचनात्मक असमानता को समाप्त करने हेतु पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ लैंगिक संवेदनशील प्रशिक्षण, कानूनी साक्षरता तथा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों को भी समान महत्व देना आवश्यक है, जैसा कि खान, भट तथा सांगमी के अध्ययन में भी संकेतित किया गया है [8]। चित्र में प्रस्तुत आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि समूह से जुड़ाव के पश्चात महिलाओं के जीवन के लगभग सभी प्रमुख संकेतकों में सुधार हुआ है, तथापि यह सुधार एकसमान गति से नहीं हुआ बचत की आदत तथा बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में सर्वाधिक सुधार देखा गया, जबकि निर्णय लेने में भागीदारी अपेक्षाकृत धीमी गति से

Global Journal of Sociology and Anthropology
Vol. 14 (1), pp. 01-10, December, 2025
ISSN: 2756-3456

बढ़ी, जो यह दर्शाता है कि पारिवारिक एवं सामाजिक शक्ति संरचनाएं वित्तीय समावेशन की तुलना में परिवर्तन के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं। यह प्रवृत्ति मध्य प्रदेश तथा ग्वालियर जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां पारंपरिक पितृसत्तात्मक मूल्य अभी भी व्यापक रूप से प्रचलित हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण चर्चा बिंदु संस्थागत स्थिरता से संबंधित है। भंजदेव एवं सहयोगियों द्वारा मध्य प्रदेश में उजागर की गई निष्क्रिय समूहों की समस्या यह दर्शाती है कि केवल समूह गठन पर्याप्त नहीं है, बल्कि निरंतर हैंड-होल्डिंग सहायता, नियमित निगरानी तथा सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का सशक्तिकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है [21]। इसके साथ ही राज्यों के बीच तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से पता चलता है कि केरल का कुडुम्बश्री मॉडल जैसी सुव्यवस्थित संस्थागत संरचनाएं मध्य भारत के मुकाबले अधिक स्थिर परिणाम देती हैं, जो यह संकेत करता है कि राज्य-स्तरीय शासन गुणवत्ता तथा प्रशासनिक समर्पण सशक्तिकरण की गति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

अंततः, यह चर्चा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि भविष्य के हस्तक्षेप कार्यक्रमों को बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसमें वित्तीय समावेशन के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता, बाजार संपर्क, कानूनी जागरूकता तथा राजनीतिक भागीदारी को समान रूप से सम्मिलित किया जाए। इसके अतिरिक्त ग्वालियर जिले पर केंद्रित सुदृढ़ अनुभवजन्य अनुसंधान, जिसमें नियंत्रण समूह तथा दीर्घकालिक अनुगमन पद्धति का प्रयोग हो, वर्तमान साहित्य में विद्यमान अंतराल को भरने हेतु अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। समग्र चर्चा से यह भी स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह मॉडल की सफलता को केवल मात्रात्मक संकेतकों तक सीमित रखकर नहीं आंका जा सकता, बल्कि इसमें गुणात्मक पहलुओं जैसे आत्म-सम्मान, सामुदायिक एकजुटता तथा पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। ग्वालियर जिले के प्रशासनिक तंत्र, बैंकिंग संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि समूह स्तर पर क्षमता निर्माण, ताकि सशक्तिकरण की प्रक्रिया व्यक्तिगत स्तर से आगे बढ़कर संस्थागत एवं संरचनात्मक परिवर्तन में परिणत हो सके।



चित्र 5: ग्वालियर जिले के विकासखंडों में स्वयं सहायता समूहों का वितरण

यह क्षैतिज स्तंभ चित्र ग्वालियर जिले के पांच प्रमुख विकासखंडों ग्वालियर शहरी क्षेत्र, मुरार, भितरवार, डबरा तथा घाटीगांव में सक्रिय स्वयं सहायता समूहों की सांकेतिक संख्या का वितरण प्रस्तुत करता है, जो उपलब्ध द्वितीयक साहित्य तथा प्रशासनिक रुझानों के आधार पर तैयार किया गया है। चित्र से स्पष्ट होता है कि शहरी ग्वालियर क्षेत्र में सर्वाधिक लगभग चौदह सौ पचास समूह सक्रिय हैं, जबकि घाटीगांव जैसे अपेक्षाकृत दूरस्थ एवं जनजातीय बहुल विकासखंड में यह संख्या घटकर लगभग छह सौ चालीस रह जाती है। यह असमान वितरण दर्शाता है कि शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में संस्थागत पहुंच अधिक सुदृढ़ है, जबकि दूरस्थ ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में समूह विस्तार हेतु अतिरिक्त प्रयासों तथा लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

6. निष्कर्ष

प्रस्तुत समीक्षा शोध पत्र ने विगत दो दशकों के प्रमुख शोध साहित्य के मेटा-विश्लेषण के माध्यम से यह स्थापित किया है कि स्वयं सहायता समूह भारत में, तथा विशेष रूप से मध्य प्रदेश एवं ग्वालियर जिले में, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले एक प्रभावी संस्थागत माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं। समीक्षित अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि इन समूहों ने आर्थिक स्वावलंबन, बचत की आदत, सामाजिक गतिशीलता तथा आत्मविश्वास में उल्लेखनीय सुधार किया है, परंतु राजनीतिक भागीदारी, संस्थागत स्थिरता तथा बाजार पहुंच जैसे क्षेत्रों में प्रगति अभी भी अपेक्षाकृत सीमित है। साथ ही यह भी उजागर हुआ कि ग्वालियर जिले पर केंद्रित प्रत्यक्ष अनुभवजन्य शोध की भारी कमी है, जिसे भरने हेतु दीर्घकालिक, बहु-पद्धतिक एवं नियंत्रण समूह आधारित अध्ययनों की तत्काल आवश्यकता है। नीतिगत दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि सरकार, बैंकिंग संस्थाएं तथा गैर-सरकारी संगठन मिलकर केवल वित्तीय समावेशन तक सीमित न रहकर कानूनी साक्षरता, डिजिटल कौशल तथा राजनीतिक जागरूकता जैसे पूरक कार्यक्रमों को भी समान प्राथमिकता दें। संक्षेप में, स्वयं सहायता समूह मॉडल ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस आधार अवश्य तैयार किया है, परंतु इसकी पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने हेतु समग्र, समावेशी तथा क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों को अपनाना नितांत आवश्यक है, जिसमें भावी शोध निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

संदर्भ सूची

[1] आर. बी. स्वैन, "क्या सूक्ष्म वित्त महिलाओं को सशक्त बनाता है? भारत में स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त साक्ष्य," इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स, खंड 23, अंक 5, पृष्ठ 541–556, 2009।

[2] एन. कुमार, के. रघुनाथन, ए. अरिएटा, ए. जिलानी, और एस. पांडे, "सामूहिक शक्ति महिलाओं को सशक्त बनाती है: भारत में स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त साक्ष्य," वर्ल्ड डेवलपमेंट, खंड 146, पृष्ठ 105579, 2021।

[3] एस. महापात्रा और बी. के. साहू, "स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में भागीदारी के निर्धारक तथा महिला सशक्तीकरण पर इसका प्रभाव," इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिव्यू, खंड 9, अंक 1, पृष्ठ 53–78, 2016।

[4] डी. के. मिड्या, ए. होता, और ए. दास, "स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तीकरण: अपनी क्षमता में वृद्धि के संबंध में एसएचजी प्रतिभागियों की धारणा," जर्नल ऑफ द इंडियन एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी, खंड 56, पृष्ठ 109–126, 2021।

[5] ए. के. श्रीवास्तव और एस. आर. मंडल, "महिला सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका," जर्नल ऑफ क्रिटिकल रिव्यूज, खंड 7, अंक 9, पृष्ठ 3279–3285, 2020।

[6] सी. टी. ब्रॉडी, टी. डी हूप, एम. वोज्टकोवा, आर. वार्नॉक, एम. डनबर, पी. मूर्ति, और एस. एल. ड्वर्किन, "क्या स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तीकरण में सुधार कर सकते हैं? एक व्यवस्थित समीक्षा," जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इफेक्टिवनेस, खंड 9, अंक 1, पृष्ठ 15–40, 2017।

[7] आर. बाली स्वैन और एफ. वाई. वॉलेंटिन, "भारतीय स्वयं सहायता समूह कार्यक्रमों में महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कारक," इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स, खंड 26, अंक 4, पृष्ठ 425–444, 2012।

[8] एस. टी. खान, एम. ए. भट, और एम. यू. डी. संगमी, "आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तीकरण पर सूक्ष्म वित्त का प्रभाव: भारत की कश्मीर घाटी में महिला स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त साक्ष्य," एफआईआईबी बिजनेस रिव्यू, खंड 11, अंक 2, पृष्ठ 231–247, 2022।

[9] टी. एल. मोयल, एम. डॉलार्ड, और एस. एन. बिस्वास, "ग्रामीण भारतीय महिलाओं का व्यक्तिगत एवं आर्थिक सशक्तीकरण: स्वयं सहायता समूह आधारित दृष्टिकोण," इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूरल मैनेजमेंट, खंड 2, अंक 2, पृष्ठ 245–266, 2006।

[10] पी. सी. परिडा और ए. सिन्हा, "भारत में स्वयं सहायता समूहों का प्रदर्शन एवं स्थिरता: एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य," एशियन डेवलपमेंट रिव्यू, खंड 27, अंक 1, पृष्ठ 80–103, 2010।

[11] एफ. टेसोरिएरो, "दक्षिण भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना," कम्युनिटी डेवलपमेंट जर्नल, खंड 41, अंक 3, पृष्ठ 321–333, 2005।

[12] के. एम. मेहता, एल. ईरानी, आई. चौधरी, टी. महापात्रा, जे. स्कूली, और एस. श्रीकांतैया, "भारत के बिहार राज्य में व्यापक स्तर पर लागू किए गए स्वयं सहायता समूहों का स्वास्थ्य पर प्रभाव," जर्नल ऑफ ग्लोबल हेल्थ, खंड 10, अंक 2, पृष्ठ 021006, 2020।

[13] एन. सग्गुर्ति, वाई. अटमाविलास, ए. पोरवाल, जे. स्कूली, आर. दास, एन. कांडे, और के. हे, "ग्रामीण भारत में प्रजनन, मातृ, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित सामूहिकता और स्वस्थ प्रथाओं पर महिला स्वयं सहायता समूहों में स्वास्थ्य हस्तक्षेप के एकीकरण का प्रभाव," पीएलओएस वन, खंड 13, अंक 8, पृष्ठ e0202562, 2018।

[14] एस. देसाई, एम. मिश्रा, ए. दास, आर. जे. सिंह, एम. सहगल, एल. ग्राम, और ए. प्रॉस्ट, "भारत में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु महिला समूहों के साथ सामुदायिक हस्तक्षेप: प्रभावों, सहायक कारकों और बाधाओं की मिश्रित-विधि व्यवस्थित समीक्षा,"

बीएमजे ग्लोबल हेल्थ, खंड 5, अंक 12, पृष्ठ e003304, 2020।

[15] एल. कौर, "पंजाब में महिला सशक्तीकरण पर स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव," पीएच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, भारत, 2014।

[16] एस. घोष, एम. एस. महापात्रा, एन. टंडन, और डी. टंडन, "महिला सशक्तीकरण के सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति: भारत में स्वयं सहायता समूहों के बीच एक अध्ययन," ग्लोबल बिजनेस रिव्यू, खंड 25, अंक 1, पृष्ठ 45–61, 2024।

[17] आर. शर्मा, "भारत में महिला सशक्तीकरण: मुद्दे और चुनौतियाँ," जेनिथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, खंड 9, अंक 2, पृष्ठ 128–134, 2019।

[18] जे. डब्ल्यू. मोमिन, "मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में ग्रामीण महिलाओं का स्वयं सहायता समूहों एवं आर्थिक सशक्तीकरण," प्रोडक्टिविटी, खंड 56, अंक 2, पृष्ठ 192–196, 2015।

[19] ए. एस. भट्ट, "गुजरात में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण पर सूक्ष्म वित्त का प्रभाव," इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, खंड 8, अंक 3, पृष्ठ 22–27, 2017।

[20] एन. डी. राठौड़, "स्वयं सहायता समूह (एसएचजी): गुजरात में जनजातीय महिला किसानों के सूक्ष्म वित्तपोषण एवं सशक्तीकरण का एक विश्वसनीय साधन," एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रिसर्च रिव्यू, खंड 30, अंक 1, पृष्ठ 125–132, 2017।

[21] ए. भांजदेव, एन. नारायण, एस. शेठ, और एम. वाल्टन, "मध्य प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह: संस्थागत निर्माण और सशक्तीकरण पर इसके निहितार्थ," 3ie कार्यपत्र संख्या 46, इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, नई दिल्ली, भारत, 2021।

[22] वाई. सुषमा, "महिला सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की प्रभावशीलता का एक अध्ययन," अध्ययन: ए जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, खंड 6, अंक 2, पृष्ठ 1–9, 2016।

[23] यू. के. धनलक्ष्मी, "साहित्य की समीक्षा: स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिला सशक्तीकरण," क्लियर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, खंड 4, अंक 10, पृष्ठ 29–34, 2013।

[24] टी. जाकिमोव और पी. किल्बी, "महिला सशक्तीकरण: भारत में स्वयं सहायता समूहों की निर्धारित रूपरेखा की एक आलोचनात्मक समीक्षा," इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज, खंड 13, अंक 3, पृष्ठ 375–400, 2006।

[25] ई. डब्ल्यू. क्रॉप और बी. एस. सुरन, भारत में बैंकों और (वित्तीय) स्वयं सहायता समूहों के बीच संबंध स्थापित करना: एक मूल्यांकन। मुंबई, भारत: नाबार्ड सूक्ष्म ऋण नवाचार विभाग, 2002।

[26] एन. ए. ए. अल-कुबाती और डी. पी. सेल्वारत्नम, "सतत विकास के साधन के रूप में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण: भारत से प्राप्त सीख," एशियन जर्नल ऑफ विमेन्स स्टडीज, खंड 27, अंक 1, पृष्ठ 45–63, 2021।

[27] एम. के. दाश, "महिला सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका: बरगढ़ में एक अध्ययन," इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज रिसर्च, खंड 2, अंक 3, पृष्ठ 15–20, 2013।

[28] एस. अहमद, "स्वयं सहायता समूह (एसएचजी): जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के गुंडाना ब्लॉक की ग्रामीण महिलाओं के लिए आशा की एक किरण," जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइकिल रिसर्च, खंड 12, अंक 9, पृष्ठ 1910–1921, 2020।

[29] बी. सुगुन, "स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण," जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, खंड 25, अंक 3, पृष्ठ 355–367, 2006।

[30] एस. रमेश, "भारत में महिलाओं के उत्थान में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका," जर्नल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड स्टडीज, खंड 4, अंक 1, पृष्ठ 1–5, 2023।